वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में क्षेत्रीय दलों की भूमिका

डॉ. अमन झा

सहायक प्राध्यापक

राजनिति विज्ञान विभाग

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

राज्य विधानसभा चुनाव का मूल्याँकन –

2014 में लोकसभा चुनाव के बाद उसी वर्ष भारत के चार राज्यों महाराष्ट्र हरियाणा मू–कश्मीर और झारखण्ड में विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनावों में कुछ विशेष बातें थी । भारतीय राजनीति की दो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की स्थिति पिछले लोकसभा चुनाव से बिलकुल उलट थी ।

कुछ ही समय पहले हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अब तक के इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करके स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था और पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई और कांग्रेस ने अपने अब तक के इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन किया।

ऐसे परिणाम के बाद यह माना जाने लगा की वर्तमान समय बीजेपी के उत्कर्ष का समय है और इसी समय उक्त चार राज्यों में विधान सभा के चुनाव हुए।

चुनाव से पूर्व इन चार राज्यों में से तीन राज्य महाराष्ट्र, झारखण्ड और जम्मू–कश्मीर में क्रमशः कांग्रेस–एनसीपी, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा–कांग्रेस, और कांग्रेस–नेशनल कान्फ्रेंस की सरकार थी । केवल हरियाणा राज्य में ही एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी । लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आये वो पुरानी स्थित से बिलकुल विपरीत थे । महाराष्ट्र में 2009 के चुनाव की अपेक्षा 2014 विधान सभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों को प्राप्त सीटों में में 5% से अधिक की वृद्दि हुई, क्षेत्रीय दलों के सीटों में भी लगभग 0.7% की वृद्धि हुई हालाँकि स्वतन्त्र उम्मीदवारों के सीट में 6% की कमी दर्ज की गई। कांग्रेस और एनसीपी की हार हुई और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी । वर्तमान समय में भाजपा–शिवसेना की गठबंधन की सरकार चल रही है जिसके मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फड़नवीस है।

हरियाणा में राष्ट्रीय दलों के सीटों में 20% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और क्षेत्रीय दलों के सीट में 18% की गिरावट आई। बीजेपी को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिला और वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार कार्य कर रही है।

झारखण्ड में राष्ट्रीय दलों को पिछले चुनाव की अपेक्षा 9% अधिक सीटें मिली वहीं क्षेत्रीय दलों को 6% कम सीटें मिली। वर्तमान समय में यहाँ भी बीजेपी और आजसू पार्टी की सरकार है जिसके मुख्यमन्त्री रघुबर दास हैं ।

जम्मू–कश्मीर के चुनाव परिणाम भी कुछ इसी तरह के रहे । पिछले चुनाव की अपेक्षा यहाँ भी राष्ट्रीय दलों को 10% अधिक सीटें मिली और क्षेत्रीय दलों को 10% कम सीटें मिली। किन्तु जम्मू–कश्मीर में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नही मिला और वर्तमान समय में जम्मू–कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू है ।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015–

वैसे तो मेरा शोध कार्य 2014 में सम्पन्न लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव पर केन्द्रित था किन्तु जनवरी–फरवरी 2015 में देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में जो परिणाम आये वो क्षेत्रीय दलों की भूमिका को एक नया रूप देने वाले थे अतः इस पर एक नजर डालना आवश्यक है।

2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली में 2013–14 में विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसमें समाजसेवी अन्ना हजारे के आन्दोलन से चर्चा में आये अरविन्द केजरीवाल की पार्टी **'आम आदमी पार्टी'** पहली बार चुनाव लड़ी और शीला दीक्षित के नेतृत्व बाली कांग्रेस पार्टी की सरकार को चुनौती देकर जीत हासिल की।

आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा में बहुमत प्राप्त नही हुआ था अतः कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई जिसके मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल थे। किन्तु जिस तीव्रता से यह पार्टी सत्ता में आई थी उसी तीव्रता से 49 दिनों बाद

अचानक केजरीवाल ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू था ।

2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी । और महाराष्ट्र, हरियाणा जम्मू–कश्मीर और झारखण्ड राज्य में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था और चुनाव में भी तथाकथित मोदी लहर के जारी रहने के कयास लगाये जा रहे थे । किन्तु दिल्ली जब 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए तो इस बार भी नतीजे अप्रत्याशित थे ।

पिछले चुनाव में 31 सीटें और 33.07% वोट प्राप्त करने वाली और वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजनीति पर पूरी तरह से छाई हुई भाजपा को जबर्दस्त झटका लगा और उसे केवल 3 सीटें ही मिली और उसका वोट शेयर भी 0.8% घट गया।

कांग्रेस को 8 सीटें और 24.55% वोट मिले थे किन्तु इस बार पार्टी का वोट शेयर 14.85% घट गया और उसे एक भी सीट नही मिली ।

इसी प्रकार पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, शिरोमणि अकाली दल और निर्दलीय को एक–एक सीते मिली थी किन्तु इस बार इनमे से किसी को एक भी सीट नही मिली। और पिछले चुनाव में 28 सीटें और 29.49% वोट पाने वाली आम आदमी पार्टी ने इस बार जबर्दस्त प्रदर्शन करते हुए 67 सीटें जीती । पार्टी को 54.3% वोट मिले जो पिछली बार से 24.8% अधिक है ।

निष्कर्ष –

उपर्युक्त तथ्यों के अध्ययन से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं –

2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नही मिला था। फलस्वरूप क्षेत्रीय दलों के सहयोग से गठबन्धन की सरकार बनी। गठबन्धन सरकार की एक सीमा होती है क्यूंकि उसके बहुत सारे घटक दल होते हैं और एक ही गठबन्धन के अलग–अलग ढलों की विचारधारा प्रायः अलग अलग ही रहती है, जिससे कई बार सरकारी नीति प्रभावित हुई । सरकार अपने वादे पूरे नही कर पाई ।

इसके साथ ही पिछली सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में लगातार घिरती गई जिससे वह उबर नही पाई ।

डॉ. मनमोहन सिंह कठोर निर्णय लेने वाले प्रधानमन्त्री की छवि नही बना पाए । पिछली यूपीए सरकार अपनी ढुलमुल रवैये की वजह से आलोचना से घिरी रही और सरकार महंगाई कम नहीं कर पाई ।

इन सब बातों से भारत की जनता को यह महसूस हुआ कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विकास तभी होगा जब एक मजबूत सरकार बने और गठबन्धन सरकार मजबूत सरकार नही होती, इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया ।

भले ही इस बार एक ही पार्टी की सरकार हो और यह कहा जाने लगा कि अब गठबन्धन सरकरों और क्षेत्रीय दलों के दिल लद गये किन्तु यह पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य इसके बिलकुल विपरीत है।

इस चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत तो मिला लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में राष्ट्रीय पार्टियों का वोट शेयर 3.54% घट गया, 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक बहुजन समाज पार्टी एक कभी सीट नही जीत पाई वहीं क्षेत्रीय दलों का वोट शेयर 11. 39% बढ़ गया ।

अतः यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस लोकसभा चुनाव में गठबन्धन सरकारों का तिलिस्म टूट गया किन्तु क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव कम नही हुआ अपितु बढ़ा है ।

इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर रहा कि वो किस राष्ट्रीय टल के साथ जुड़े थे? भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले क्षेत्रीय दलों को लाभ हुआ और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले क्षेत्रीय दलों को नुकसान हुआ ।

सबसे बड़ा चमत्कार दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ । चुनाव से पहले सवर्त्र मोदी लहर की बात की जा रही थी किन्तु जब परिणाम आये तो जनता ने केजरीवाल को पूर्ण बहुमत दिया।

इससे यह बात सिद्ध होती है कि अभी भी क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कम नही हुआ है और मतदाता अब जागरूक हो गया है, वो किसी लहर में या किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में नही अपितु अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के हिसाब से अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगा है।